(3) उन सभी टंककों के लिये जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। इस प्रयोजनार्थ स्वयं मंत्रालय में ही एक हिंदी टाइपिंग यूनिट बनाई गई है।

(4) मन्त्रालय में हिंदी आशुलिपिकों का एक पूल बनाय गय है जिनकी सेवायें अधिकारी हिंदी टाइप टिप्पण और प्रारूपण लिखवाने में ले सकते हैं।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिंदी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर 229 फाइलों में हिंदी में काम किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय के अधीन 9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम काम कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली में अनेक अनुभाग 20 से 40 तक आना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं परियोजना व उपस्कर निगम तथा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के एक-एक अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। मंत्रालय के अन्य प्रमुख संगठनों के जिन अनुभागों में 50% से अधिक कार्य हिंदी में हो रहा है वे हैं प्रशासन कार्मिक, लेखा, जनसंपर्क तथा सम्पदा।

(घ) अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या 4 है जिनके लिये हिन्दी साफ्टवेयर भी प्राप्त किया गया है। टेलेक्स मशीनों (अंग्रेजी) की संख्या 4 है। इस मंत्रालय में कोई टेलीप्रिंटर नहीं है।

दस्तावेज का हिन्दी में अनुवाद

76. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द विकल :

क्या जल ससाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय में राजभाषा की घोर उपेक्षा की जा रही है और "क" "ख" तथा "ग" क्षेत्रों की तो बात ही क्या "क" क्षेत्र में स्थित मुख्यालयों तक में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन नहीं किया जा रहा है तथा विशेष कर प्रतिवेदनों, अध्ययन प्रतिवेदनों और इसी प्रकार के अनेक दस्तावेजों का हिन्दी में न तो अनुवाद किया गया है और न ही किया जा रहा है ; और

(ख) अंग्रेजी में तैयार किये गये दस्तावेजों, प्रतिवेदनों, अध्ययन प्रतिवेदनों आदि की संख्या कितनी हैं और ये किस प्रकार के हैं तथा इनमें से कितनों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) समय समय पर कई प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं जिनमें रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों हेतु आन्तरिक प्रयोग के लिए तकनीकी स्वरूप के प्रतिवेदन भी सम्मिलित हैं। इनमें समय समय पर गठित अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों के प्रतिवेदन, आयोगों के प्रतिवेदन, विभिन्न तकनीकी समितियों के प्रतिवेदन शामिल हैं। इनमें से अधिकांश प्रतिवेदनों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है।

राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन

77. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक 13 उपक्रमों/ कम्पनियों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति क्या हैं ;

(ख) "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित कंपनियों में कितने प्रतिशत कार्य राजभाषा में किया जा रहा है ;

(ग) धारा 3 (3) के पालन के संबंध में स्थिति क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां राजभाषा अधिनियम की धारा 10 (4) और 8 (4) कार्यान्वित कर दी गई है ; और

(घ) उन स्थानों के, विशेषकर "क" क्षेत्र में स्थित उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां शत प्रतिशत कार्य राजभाषा में किया